दैनिक

सुप्रीम न्यूज

हिन्दी समाचार पत्र

आर एन आई नंबर UPHIN/2010/33252

जनता का अखबार

वर्ष : 13 | अंक : 321 | गौतमबुद्धनगर, | गुरूवार, 26 जनवरी 2023 | उत्तर प्रदेश से प्रकाशित | पृष्ठ : 04 | मूल्य : 05 रूपये मात्र

दरोगा तो बताएंगे नही तमंचों और कारतूसों की मंडी कहां है ?

गौतमबुद्धनगर के मरे हुए मीडिया में दम नही की पुलिस की कार्य शैली पर सवाल उठा सके- संजय भाटी

गौतमबुद्धनगर : रेंचो नाम के एक अपराधी से चार साल में चार अलग-अलग मामलों का खुलासा करते हुए गौतमबुद्धनगर नगर पुलिस द्वारा चार तमंचे और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इनमें से तीन तमंचे और चार कारतूस 315 बोर के हैं। एक तमंचा और कारतूस 12 बोर का है। ये हम नही कह रहे हैं ये सब गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट की पुलिस कह रही है। बल्कि यह सब कहने सुनने तक सीमित नही है ये सब तो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। इसलिए ये सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन ही होंगे। वैसे भी रेंचो से हर मामले में तमंचा व कारतूस पुलिस के द्वारा बरामद किये गये हैं। एक बार एचसीपी स्तर के पुलिस कर्मी द्वारा मु0अ0सं0 327/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर (बनाम वहीद उर्फ रेंचो) दिनांक 09/05/2018 को एक तमंचा 315 बोर और दो कारतूस लुउढ अनार सिंह यादव द्वारा बरामद किये गये थे।

इस के अलावा तीन बार दरोगाओं द्वारा ये जान लेवा हथियार बरामद किए हैं। इसलिए इस बात की भी को गुंजाइश नही है कि तमंचों और कारतूस अन्य बहारी व्यक्ति ने उस पर फर्जी तरीके बरामद करा कर उसे फंसा दिया हो ?

मु0अ0सं0 130/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर (बनाम वहीद उर्फ रेंचो) दिनांक 16/02/2020 को एक तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस नाल में फंसा हुआ दरोगा योगेश सिंह मलिक द्वारा बरामद किया गया था।

मु0अ0सं0 327/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर (बनाम वहीद उर्फ रेंचो) दिनांक 08/09/09/2022 को उपनिरीक्षक महिपाल सिंह द्वारा एक तमंचा

12 बोर न एक कारतूस बरामद किया गयो

मु0अ0सं0 23/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर (बनाम वहीद उर्फ रेंचो) दिनांक 12/01/2023 को एक तमंचा 315 व एक मिस कारतूस उप निरीक्षक विकास कुमार द्वारा बरामद किया गया है। क्या कभी किसी अधिकारी, नेता या फिर समाज सेवी संस्थाओं या फिर किसी मीडिया संस्थान या फिर किसी पत्रकार ने इस पर सवाल उठाए ?

आखिर मौत का सामान आता कहां से है ? पुलिस के जांबाजों द्वारा कभी खुलासा किया कि तमंचों और कारतूसों की आपूर्ति अपराधियों को कहां से हो रही है ? आए दिन फिल्म की स्क्रिप्ट लिख कर मरे हुए मीडिया को परोस दी जाती है। सारे मुर्दे पुलिस का गुणगान करके ही अपने आप को पत्रकार साबित करने में लगे रहते हैं।

क्या ये चिंता का विषय नही की जिले में आए दिन बेहिसाब तमंचे और कारतूस बरामद होते हैं?

पुलिस वाह वाही लूटने के लिए प्रेस नोट जारी कर देती है। जिले भर के पत्रकारों में से कोई पूछने को तैयार नही है कि आखिर तमंचे किस जादूगर की पिटारी से निकल रहें हैं? पुलिस अपराध रोकने पर ध्यान देने के बजाए धमाके दार खबर तैयार करने पर ध्यान देती है। पत्रकार और पुलिस दोनों ने केवल जनता को मुर्ख बना रहे हैं बल्कि न्यायालयों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं।

हर रोज सुबह से शाम तक अकेले गौतमबुद्धनगर पुलिस पांच-सात तमंचे और कारतूस बरामद कर देती है। महीने भर में 100 से 150 तक और यदि इसी आंकड़े को साल भर पर जोड़ दें तो हजार से पंद्रह सौ को पार कर जाएगा।

कितनी बेशर्मी और ढिठाई की बात है कि अपराध की जड़ तक पहुंचने का कोई प्रयास तक भी नही किया जाता। बस दनादन फेंकने से मतलब है

कमिश्नरेट पुलिस की मीडिया सेल द्वारा जारी विज्ञप्ति पर नजर डालने भर से पता चलता है कि रेंचो जब भी पुलिस ने पकड़ा तभी एक नए तमंचे और एक या दो कारतूसों के साथ लेकिन पकड़ने वाले दरोगाओं ने कभी भी रेंचो से यह नही पूछा कि बार-बार तमंचे और कारतूस कौन सी मंडी से लाएं जाते हैं। जब हम लोगों ने रेंचो से इस सवाल का जबाव जानना चाहा तो उसने दरोगा की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये सब दरोगा को पता है आप में दम है तो दरोगा से पता करो।

पत्रकारों पुलिस के जयकारे लगाओ वरना फर्जी मुकदमें भी दर्ज होंगे और जेल भी जाओगे

गौतमबुद्धनगर। पिछले महीने भर से गौतम बुध नगर पुलिस द्वारा गांजा तस्करों की धरपकड़ जारी है जिसमें 4 दर्जन से अधिक गांजा तस्कर गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। गांजा तस्करों की गिरफ्तारी के सटीक आंकड़े देना तो संभव नही है क्योंकि जिले की जांबाज पुलिस कभी भी किसी भी मामले में आरटीआई के माध्यम से कोई भी सूचना देने से इंकार कर देती है। वैसे तो पुलिस आए दिन प्रेस कांफ्रेंस और विज्ञप्तियां जारी कर सभी ऐसे कानूनों की धज्जियां उड़ती है जिनका हवाला सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना को देने से इंकार करते समय करती है। वैसे यह तो साफ है कि गांजा तस्करों पर कार्रवाई गौतम बुध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की तैनाती के बाद तेजी पकड़ती नजर आ रही है। लेकिन अभी भी इसमें एक बड़ा पेंच यह है कि सभी कार्रवाही पुलिस द्वारा स्वयं की गई हैं। इसमें ऐसा ना के बराबर है कि किसी समाजसेवी पत्रकार

या यूं कहें कि आम नागरिक की शिकायत पर किसी गांजा तस्कर की गिरफ्तारी की गई हो। बल्कि यदि किसी गांजा तस्कर या अन्य किसी तरह के अवैध कारोबार की शिकायत आमजन द्वारा दी जाती है तो पुलिस एकाएक शिकायत के विरोध में खड़ी हो जाती है। पब्लिक की शिकायत पर शायद पुलिस को अपनी तौहीन महसूस होती है। अब इसका कारण क्या हो सकता है ? ये समझ से बाहर है। लेकिन जब पुलिस खुद कुछ गांजा तस्करों को गिरफ्तार करके उनके फोटो, वीडियो व अधिकारियों की बाइट के वीडियो जारी करती है। कई बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करके यह साबित करने की कोशिश करती है कि पुलिस गांजा तस्करों को लेकर सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ऐसे करके जनता को यह संदेश देने की कौशिश करती है कि पुलिस जिले से गांजा तस्करी को खत्म कर देगी।

अखबारों में सोशल मीडिया वेबसाइटों पर पुलिस द्वारा दी गई इस तरह की खबरों को पढ़कर कई बार कुछ आमजन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि पुलिस वास्तव में गांजा तस्करी के खिलाफ अभियान चला रही है।

शेष खबर 3 पर

संपादकीय

सुप्रीम न्यूज परिवार की ओर से गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

भले ही हम 74 वा गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं पत्रकारों ध्यान रहे तमंचा किसी से भी बरामद हो सकता है

संपादक की कलम से

26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ किया गया था। जिसके उपलक्ष्य में आज हम 74 वा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। दोनों राष्ट्रीय स्तर की बात है। गणतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र का अभिप्राय उस राज्य या राष्ट्र जिसमें समस्त राज्यसत्ता जनसाधारण के हाथ में हो और वे सामूहिक रूप से या अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन और न्याय का विधान करते हों। सीधे शब्दों में कहें तो हम संविधान दिवस यानी कानून दिवस मना रहे हैं। संक्षेप में कहें तो जन सामान्य को देश में न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान देने वाले संविधान को लागू होने की खुशियां मना रहे हैं।

ध्यान रहे हम 74 वा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं पत्रकार ही क्यों ना सही। रहना तो पुलिस के डंडे के नीचे है

देश के आंतरिक भागों में संविधान और कानून को लागू करने की पहली जिम्मेदारी या पहली सीढी थाना पुलिस होती है। मतलब गरीब जनता को न्याय की उम्मीद थाने से ही होती है।

गरीब के पास न्यायालयों तक पहुंचने का न तो ज्ञान होता है और न ही बजट। जो व्यक्ति सरकारी राशन की दुकान पर राशन के लिए खड़ा हो उसकी जिन्दगी में उसकी चुनी हुई सरकार, संविधान और सुप्रीम कोर्ट की नुमाइंदगी पुलिस का सिपाही ही करता है। गरीब के पास दूसरे कोई विकल्प ही नही होते। गरीब तो पुलिस के अधिकारियों तक भी नही पहुंचता। गरीब के लिए वकीलों और न्यायालयों तक का रास्ता केवल और केवल पुलिस के द्वारा ही पहुंचता है। वर्दी पहने प्रत्येक सिपाही को इस वास्तविकता को भलीभांति समझना चाहिए।

भले ही हिरासत में मौत के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। पिछले तीन सालों की मीडिया रिपोर्टों को देखें तो 1318 लोगों की मौत के आंकड़े हमारे सामने हैं।

यहां हम केवल अपने जिले की बात करना चाहते हैं । हिरासत में मौत के मामले में गौतमबुद्धनगर में बहुत गनीमत है यहां के जांबाज तो मुठभेड़ के नाम पर सट-ीक निशाना साधते हैं। यहां की पुलिस प्रदेश भर में सबसे अधिक कमाऊ और जांबाज है। पिंडलियों में गोली बहुत लगती है पर सीने में बहुत कम। ध्यान रहे हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं

गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। यहां जितना गरीबों को सताया जाता है उतना ही धन कमाया जाता है। यानी मुठभेड़ से अपराध की रेटिंग तो आज तक कम नही हुई पर पुलिसिंग की रेटिंग जरूर अप हो जाती है।

यहां सब चमत्कारी मामले हैं। गौतमबुद्धनगर पुलिस चमत्कारों में मामले में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर धाम सरकार) से भी ज्यादा करिश्माई शक्तियों का प्रदर्शन आए दिन करती है । धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कितने भी चमत्कार क्यों न कर ले पर हमारे जिले के दरोगाओं की शक्ति को चुनौती नही दे सकते। हमारे दरोगाओं की गोली सीधे बदमाशों की पिंडलियों में इच्छित जगह पर ही लगती है। हमारे दरोगा अच्छे अच्छे के पास से तमंचा और कारतूस बरामद कर सकते हैं। अधिकारियों के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत तमंचा, कारतूस, गांजा, अवैध शराब और न जाने क्या-क्या बरामद कर सकते हैं। ध्यान रहे हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं।

एक से बढ़कर एक विशेष और अद्भुत क्षमता हमारे दरोगाओं में हैं । उच्चाधिकारी जितने ईमानदार होंगे उनके नाम पर दरोगा और सिपाही अपनी रेटिंग हाई कर देंगे।

मुठभेड़ों के मामलों में तो किसी भी अरे गरे से खुद की पिस्टल छिनवा कर भी उसके पैर में निशाना साध देते हैं। मुठभेड़ों के नाम पर दो मुकदमे तो पलक झपकते ही बढ़ा देते हैं। एक आर्म्स एक्ट और दूसरा हत्या के प्रयास का। जबकि हमारे यहां के थानों में जनता की सही घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज नही होती। ध्यान रहे हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं।

छत्रसाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने फहराया तिरंगा

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की तरफ से छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह का बुधवार को आयोजन हुआ। गणतंत्र दिवस पूरे देश में 26 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन दिल्ली में ये आयोजन 25 जनवरी को ही हो जाता है। आज इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराया, उसके बाद परेड के निरीक्षण के लिए निकले। दिल्ली पुलिस की खुली जीप में सवार मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस, महिला बटालियन सहित कई स्कूलों के परेड का निरीक्षण किया।

अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम एक तरफ 74 वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस राजगुरु समेत ढेरों नाम हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को स्वतंत्रता दिलाई थी। आजादी दिलाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ी है। स्वतंत्रता सेनानियों ने जनतंत्र-गणतंत्र को कायम रखने और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी आजादी के बाद की पीढ़ियों पर सौंपी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा आज देश के एक प्रतिष्ठित अखबार में छपा है कि चीन ने हमारे देश की कुछ जमीन के हिस्से पर कब्जा कर लिया। सभी भारतवासियों के लिए चिंता का विषय है। बॉर्डर पर बहादुरी के साथ हमारे देश के सैनिक चीन का मुकाबला कर रहे हैं। प्रत्येक देशवासी का फर्ज बनता है कि इस लड़ाई में हम अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। प्रत्येक देशवासी का फर्ज बनता है कि हम चीन का बहिष्कार करें और सख्त संदेश दे।

इतना ही नहीं आगे मुख्यमंत्री ने चीन को आड़े हाथ लेते हुए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ चीन हमें आंख दिखा रहा है। हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। दूसरी तरफ हम चीन से अपना व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं। 2020 में हम लोगों ने चीन से 65 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा। 2021 में हमने चीन से 95 बिलीयन डॉलर का सामान खरीदा। हम तो चीन को और अमीर बनाते जा रहे हैं। हमारे ही पैसे से चीन हथियार खरीदता है और अपनी सेना में सैनिकों की भर्ती करता है और हमारे खिलाफ खड़ा होता है, जो सामान हम चीन से खरीद रहे हैं अगर उसका उत्पादन भारत में होगा तो देशवासियों को रोजगार मिलेगा। सरकार को टैक्स मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। साथ ही चीन को सख्त संदेश भी जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा बीते 6 सालों के दौरान 12 लाख व्यापारी व्यवस्थाओं से दुखी होकर भारत छोड़कर अन्य देशों में जा चुके हैं।

अगर भाजपा की हिम्मत है तो वो अपनी हार स्वीकार करें और मेयर के चुनाव होने दे-सिसोदिया

नई दिल्ली। एमसीडी चुनावो में आम आदमी पार्टी से बुरी तरह हारने के बाद अब भाजपा जब मेयर चुनाव में भी अपना सूपड़ा साफ होते देख रही है तो बेईमानी और गुंडागर्दी पर उतर आई है और सदन छोड़ के भागने लगी है। मेयर चुनाव के दौरान आज एक बार फिर भाजपा के पार्षदों ने सदन में हंगामा किया और भाजपा की प्रोटेम स्पीकर ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। इसका विरोध करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर भाजपा की हिम्मत है तो वो अपनी हार स्वीकार करें। अगर भाजपा वाले लोकतंत्र और संविधान में थोडा भी यकीन रखते है तो इस बात को स्वीकार करें कि दिल्ली कि जनता ने उन्हें हरा दिया है और वो मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव होने दे।उन्होंने कहा कि पहले तो हार के डर से भाजपा एमसीडी चुनावों को टालती रही उससे दूर भागती रही। जब चुनाव हुआ और जनता ने इन्हें हरा दिया तो अब ये मेयर के चुनाव से दूर भाग रहे है। भाजपा लोकतंत्र का सम्मान करें और उनमे हिम्मत है तो आज ही मेयर का चुनाव करवाए। आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद, विधायक और सांसद सदस्य सदन में बैठे है। सदन द्वारा इस मीटिंग को तुरंत वापिस बुलाया जाये और आज ही मेयर का चुनाव करवाया जाये।

आगे सिसोदिया ने कहा कि, आज आप के पार्षदों ने सदन में शांतिपूर्ण तरीके से भाग लिया। सभी चाहते थे कि मेयर के चुनाव होने चाहिए। आप के सारे पार्षद शांतिपूर्ण तरीके से पूरी प्रक्रिया के दौरान बैठे रहे लेकिन भाजपा ने जान बुझकर अपने पार्षदों से हंगामा करवाया और पहले 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करवाया और उसके बाद प्रोटेम ऑफिसर ने आकर अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित कर दिया। ये साफ है कि भाजपा चुनाव से भाग रही है।

सिसोदिया ने मांग करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद, विधायक और सांसद सदस्य सदन में बैठे है। सदन द्वारा इस मीटिंग को तुरंत वापिस बुलाया जाये और आज ही मेयर का चुनाव करवाया जाये।

भाजपा मेयर का चुनाव हार रही थी इसलिए सदन स्थगित कर दिया : सिंह

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा मेयर का चुनाव हार रही थी इसलिए सदन स्थगित कर दिया। उपराज्यपाल एलजी आज ही चुनाव का वक्त निर्धारित करें। आम आदमी पार्टी के पास 151 पार्षद, विधायक और सांसद का समर्थन है जबकि भाजपा के पास सिर्फ 111 पार्षद और सांसदों का समर्थन है। आम आदमी पार्टी के पास भाजपा के मुकाबले 40 संख्याबल ज्यादा है। प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल और गृहमंत्री आकर देख लें कि 'आप' के पास मेयर चुनाव के लिए 151 वोट हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने खतरनाक प्रयोग शुरू कर दिया है, अगर ये चुनाव नहीं जीतेंगे तो मेयर नहीं बनने देंगे। भाजपा विधानसभा-लोकसभा चुनाव में हार गई तो स्पीकर-सीएम-पीएम नहीं बनने देगी। ऐसे फिर लोकतंत्र में जनता के जनादेश का क्या मतलब रह गया ? केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, पूर्व मंत्री हर्षवर्धन की मौजूदगी में भाजपा के पार्षद, 'आप' महिला पार्षदों के साथ मारपीट कर रहे थे। विधायक आतिशी ने कहा कि भाजपा हार गई, तो क्या मेयर नहीं चुना जायेगा? दिल्ली की जनता को एमसीडी की सरकार चाहिए। उपराज्यपाल से अपील है कि नए मेयर के चुनाव का वक्त निर्धारित करने की फाइल पर तुरंत साइन करें। आज ही चुनाव कराएं, हम सभी यहां बैठे रहेंगे। विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा डरकर मेयर चुनाव से भाग रही है और अवैध तरीके से एमसीडी पर कब्जा करना चाहती है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि 'आप' के पास नंबर नहीं हैं, हम मीडिया के सामने 'आप' पार्षदों की हाजिरी कराएंगे। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली के दो करोड़ लोगों ने जनादेश दिया है, यह उसका गला घोंटना और अपमान करना है। आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद, 13 विधायक और 3 सांसद को वोटिंग के अधिकार हैं। इसके अलावा एक और पार्षद हमारे साथ होने से 151 वोट हमारे मेयर उम्मीदवार के पक्ष में थे। भले एलजी, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री आ जाएं। हम सभी 151 आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक, सांसद मेयर चुनाव में वोटिंग देने के लिए मौजूद है।

सरकार को बाईपास कर हर फैसला लेने के अति उत्साह में एलजी ने खड़ा कर दिया कानूनी संकट - मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली। एलजी और मुख्य सचिव ने हर मामले में दिल्ली की निर्वाचित सरकार को दरकिनार करने के अपने अति उत्साह से ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि राज्य के खिलाफ गंभीर अपराध करने के कई आरोपी छूट सकते हैं। आईपीसी की धारा-196 कहती है कि राज्य के खिलाफ किए गए अपराधों के मामले में कोई भी कोर्ट राज्य सरकार के अनुमोदन या मंजूरी के बिना ऐसे किसी भी मामले का संज्ञान नहीं लेगी। कई जघन्य अपराध इसी श्रेणी में आते हैं। दिल्ली सरकार के विधि विभाग के अनुसार, इस कानून में राज्य सरकार का मतलब निर्वाचित सरकार है। इसका मतलब यह है कि प्रभारी मंत्री ही सक्षम प्राधिकारी हैं और इन सभी मामलों में मंत्री की मंजूरी आवश्यक है। मंत्री की मंजूरी के बाद फाइल एलजी के पास यह तय करने के लिए भेजी जाएगी कि क्या वे मंत्री के फैसले से अलग हैं या वे इसे राष्ट्रपति को भेजना चाहते हैं।

कुछ माह पहले तक यही प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। लेकिन पिछले कुछ महीने से मुख्य सचिव ने मंत्री को दरकिनार करते हुए इन सभी फाइलों को सीधे उपराज्यपाल को भेजना शुरू कर दिया। एलजी साहब ने भी इन सभी मामलों में अनुमोदन दे दिया, जबकि उनके पास अनुमोदन देने का अधिकार नहीं हैं। लिहाजा, पिछले कुछ महीनों में ऐसे सभी आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए दी गई मंजूरी अमान्य है और जब आरोपी इस बात को कोर्ट में उठाएंगे, तो उन्हें छोड़ा जा सकता है। उपमुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने मुख्य सचिव को बुधवार शाम 5 बजे तक ऐसे सभी मामलों की सूची पेश करने का निर्देश दिया है, जिन मामलों में उनसे मंजूरी नहीं ली गई है।

इस तरह, मुख्य सचिव और एलजी ने दिल्ली सरकार के लिए यह अजीब स्थिति पैदा कर दी है। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बाईपास करते हुए हर एक फ़ैसला लेने के अतिउत्साह में एलजी साहब ने एक कानूनी संकट खड़ा कर दिया है।

पुलिस व पर्स/मोबाइल लुटेरे बदमाशों के बीच हुयी मुठभेड़, 2 लुटेरे गिरफ्तार

नोएडा। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने सेक्टर 18 में एचडीएफसी बैंक के पास चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर पीछा करने के उपरांत नाले के किनारे सेक्टर 16ए पर पुलिस मुठभेड़ में शातिर पर्स/मोबाइल लुटेरे (1) सचिन पुत्र सुरेंद्र निवासी 21/456 कल्याणपुरी थाना कल्याणपुरी दिल्ली उम्र 28 वर्ष (2) निशांत पुत्र नरेश निवासी 11 बटे 216 कल्याण पुरी थाना कल्याण पुरी दिल्ली उम्र 24 वर्ष को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 4 मोबाइल फोन संदिग्ध, चोरी की एक मोटरसाइकिल व 2 तमंचे 315 बोर, 2 खोखा व 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया है की गिरफ्तार अपराधी आने जाने वाले युवक व महिलाओं को धक्का मारकर पर्स व मोबाइल छीनने की घटना कारित करते थे। इनके द्वारा करीब 10 दिन पहले सेक्टर 18 में एक महिला को धक्का मारकर उसका पर्स छीन लिया गया था। अभियुक्त सचिन पुत्र सुरेंद्र एवं निशांत पुत्र नरेश उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली, गाजियाबाद एवं गौतम बुध नगर में लूट आदि के कुल 16 अभियोग पंजीकृत हैं।

स्वात्वाधिकारी **मुद्रक, प्रकाशक संजय भाटी ने** वत्स आफसैट मुद्दा हाऊस सी ब्लाक बारातघर के सामने चौडा रघुनाथपुर सेक्टर 22 नोएडा गौतमबुद्धनगर से मुद्रित एवं सेवा सदन देवला , ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित किया । RNI.NO.UPHIN/2010/33252, Mob. 9811291332 किसी भी विवाद के लिए पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी। **संपादक- मधु**

क्या पुलिस गणतंत्र दिवस पर भी मेले में जुआ चलवाएगी?

बहलोलपुर के बाद फिर कहां चलेगा मेले के नाम पर जुआ

नोएडा। गौतम बुध नगर में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो बाल मनोरंजन मेला, होली मेला, दीपावली मेला, या दूसरे धार्मिक उत्सवों के नाम पर चलने वाले मेलों, गणतंत्र दिवस मेला, स्वतंत्र दिवस मेला, ईद मेला, नव वर्ष मेला आदि नामों से मेलों का आयोजन कर मेलों की आड़ में खाईबाडी करता है। मेलों में खाईबाडी करने वाले लोगों का उद्देश्य जिले में रह रहे प्रवासी मजदूरों को तरह तरह से जुआ चल कर उनके पैसे की ठगी करना होता है। वैसे ये कोई नई बात नही है। ये एकदम आम बात है। अधिकांश मेलों में जुआ चलाया जाता है। बहलोलपुर मेले में खाईबाडी करने में बाबू पुत्र रामभूल, भुपेंद्र पुत्र रामभूल, विनोद, बिट्टू, निक्की व दीदी बाबू के चाचेरे भाई, घनश्याम बाबू का जीजा, धरमी, कमल, अजय पुत्र पप्पू के अलावा कुछ तथाकथित नेता शामिल हैं। ये लोग अपने आप को जिले के पत्रकारों के रिश्तेदार बताते हैं। बाबू और उसके रिश्तेदारों द्वारा छिजारसी, छलेरा, सिलारपुर, सेक्टर 46 और पिछले महीने सरफाबाद में भी इस तरह मेले में खिलौने की दुकान पर पर्ची लगा कर जुआ चलाते

रहे हैं। सरफाबाद में मेले में जुआ चलाने को लेकर मुकदमा भी दर्ज हुआ था लेकिन उसमें भी बाबू और उसके रिश्तेदार पुलिस से सांठगांठ के चलते बच गए थे। यह गिरोह न केवल गौतम बुद्ध नगर जिले में बल्कि आसपास के जिलों में भी पिछले लंबे समय से मेलों का आयोजन कर खाईबाड़ी करता रहा है। इस गिरोह की जगह जगह आम जनता या कुछ जन पक्षीय पत्रकारों द्वारा ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया माध्यमों व लिखित रूप में पुलिस के उच्चाधिकारियों से शिकायत की जाती रहती हैं। लेकिन मेलों में चलाए जा रहे जुआ के मामले में पुलिस द्वारा कभी भी कोई ठोस कार्रवाई नही की जाती। बल्कि पुलिस द्वारा कार्यवाही करने के बजाए मेला संचालकों का बचाव करते आमतौर पर देखा जाता है। जबकि मेलों में जुआ चलाए जाने से संबंधित विडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर वायरल होती रहती हैं। जबकि पुलिस हमेशा ही मेलों में किसी प्रकार के जुआ आदि के न चलाएं जाने की रिपोर्ट ट्विटर या फिर लिखित शिकायतों के जबाब में लगाती

नोएडा पुलिस के अधिकारियों को बताना होगा कि एलपीजी गोदाम और हाईटेंशन लाइन के पास मेले की परमिशन किस आधार पर दी गई है ? मेले में झुलों का फिटनेस और बैठने वाले लोगों का इंश्योरेन्स नही है। आग से निपटने का नही है कोई इंतजाम। मेले में सीसीटीवी कैमरे तक नही लगवाए गए हैं। मेले में कोई हादसा हुआ तो क्या परमिशन देने वाले पुलिस के अधिकारियों जिम्मेदारी लेंगे। मेले की परमिशन को लेकर और भी कई बड़े सवाल है।

रही है। जिससे पुलिस की संलिप्तता सबके सामने आती रहती है।

फिलहाल नोएडा के सैक्टर 63 थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव में चलाए जा रहे मेले के बारे में भी जुआ चलाएं जाने की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता संजय भाटी, सुनील, विनय और कुछ अन्य द्वारा जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर को दी गई शिकायत में बाबू और उसके कुछ रिश्तेदारों द्वारा बहलोलपुर मेले में जुआ चलने की शिकायत दी गई। शिकायतकताओं द्वारा अपने ट्विटर से व WhatsApp से भी पुलिस के अधिकारियों को शिकायत व जुआ चलाने के संबंध में विडियो भी भेजें गए हैं। नोएडा पुलिस शिकायतकर्ता के आरोपों को गलत बात रही है

जबकि शिकायतकर्ता संजय भाटी ने पुलिस की जांच को झूठा बताते हुए सार्वजनिक रूप से पुलिस की जांच को चुनौती देते हुए उत्तर प्रदेश व जिला पुलिस के अधिकारियों से कहा है कि यदि उसकी शिकायत झूठी है तो झूठी शिकायत दर्ज कराने के मामले में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएं।

सरकारी राशन पर राशन डीलरों ने गरीबों के हिस्से में कटौती कर मचा दी लूट.

खाद्य पूर्ति विभाग अधिकारी बेसुध, औचक निरीक्षण करने की नही है फुर्सत

(सुप्रीम न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट)

जनपद गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में सभी राशन डीलरों ने सरकारी राशन में से प्रत्येक राशन कार्ड धारक को राशन कम यूनिट करके दिया जा रहा है। नोएडा में गरीब तबके के लोग डर और राशन डीलरों की दबंगई के कारण शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। इतना ही नही जैसे तैसे कोई भी आम नागरिक कम यूनिट दे रहे राशन डीलर की शिकायत खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारीयों से करते हैं तो विभाग के अधिकारी नजरअंदाज कर देते हैं। गरीब जनता रहे राशन डीलरों की शिकायतें पत्रकारों को भी देती रहती है। लेकिन अधिकांश पत्रकार भी प्रवासी मजदूरों की शिकायतों को गंभीरता से नही लेते। सुप्रीम न्यूज ने राशन डीलरों के यहां लोगों के साथ सर्वे किया तो पाया कि बहुत से राशन डीलर राशन कार्ड धारकों को राशन कम देते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है तो उसे धमकाकर

भगा देते हैं। सदरपुर अघापुर, सेक्टर 11, छलेरा, भंगेल, सलारपुर, बरौला आदि के अधिकांश कोटेदारों का प्रवासी मजदूरों के साथ यही रवैया रहता है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि नोएडा में राशन डीलर खाद्य पूर्ति विभाग की कार्यवाही से बेखौफ होकर खुलेआम धड़ल्ले से राशन कार्ड धारकों को कम राशन दे रहे हैं जिसमें साफ तौर से लापरवाही खाद्य पूर्ति विभाग अधिकारियों की दिखाई दे रही है। आखिरकार कुंभकरण की नींद सो रहे खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों की नींद कब खुलेगी?

गरीब जनता के हकों को डकार रहे राशन डीलरों पर अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण कर कार्यवाही क्यों नही की जाती?

पत्रकारों पुलिस के जयकारे लगाओ.....

जिसके चलते कुछ आमजन, समाजसेवी, पत्रकार भी ट्विटर आदि पर अपने आसपास हो रही गांजे की बिक्री व दूसरे मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर पुलिस को सूचना दे देते हैं। जिसके बाद ऐसी सूचनाओं के सार्वजनिक होने पर पुलिस का जो रवैया देखने को मिलता है उसे देखकर यह साबित हो जाता है कि पुलिस किसी नए अधिकारी के आने मात्र से खानापूर्ति के लिए हर थाना क्षेत्र से दो, चार गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर आमजन व अपने अधिकारियों की नजर में अपने चेहरे पर भ्रष्टाचार और गैरकानूनी गतिविधियों की कालिख को पोंछ रही है। जिसको अधिकारी भी भलीभांति समझते हैं। इस तरह कुछ गिरफ्तारियां करके पुलिस यह साबित करने में लगी रहती है कि जिले से गांजा तस्करों का सफाया करने की कार्रवाई की जा रही है।

जन शिकायतों के आधार पर कभी भी पुलिस किसी भी अवैध धंधे में लिप्त व्यक्ति के वीडियो आदि देने के बावजूद भी कार्यवाही नही करती है। बल्कि पुलिस द्वारा जन शिकायतों को किसी न किसी तरह से झूठा साबित कर दिया जाता है। जो इस बात का पुख्ता सबूत होता है कि पुलिस खानापूर्ति के लिए ही कुछ छोटे-मोटे अपराधियों को गिरफ्तार करती है। जन शिकायतों पर पुलिस के रवैयें को देखकर यह कहने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है कि पुलिस की अवैध कारोबारियों के साथ सांठगांठ होती है।

ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई हुए शिकायतों पर पुलिस को उनके निस्तारण में अपराधियों की वकालत करते हुए देखकर सर्वजनिक रूप से इस बात का आभास होता है कि पुलिस स्वयं अवैध कारोबारियों से जुड़ी हुई होती है। कई बार तो यदि शिकायतकर्ता कोई सामान्य व्यक्ति या कमजोर प्रवृत्ति का है तो पुलिस शिकायतकर्ता पर झूठी शिकायत करने, पुलिस की बदनामी करने आदि के मुकदमे दर्ज कर देती है। गौतमबुद्धनगर ये कोई नई बात नही है। जब पुलिस की अपराधियों से मिली भगत और गैरकानूनी गतिविधियों को उजागर करने पर पत्रकारों पर मुकदमें दर्ज किए गए हैं । कई मामलों में तो पुलिस जन सामान्य और पत्रकारों को फर्जी मामले में फंसा कर खुला संदेश प्रचारित करती है कि पुलिस के मामलों में हस्तक्षेप करोगे तो फर्जी मुकदमें भी दर्ज होंगे और जेल भी जाओगे। ऐसे मामलों की लंबी फेहरिस्त है। बीते वर्ष पत्रकार अनुज गुप्ता पर पुलिस की गांजा तस्करों से संलिप्तता को खोलने वाले एक वीडियो के कारण मुकदमा दर्ज किया गया । ये सवाल हम गणतंत्रता दिवस पर विशेष रूप से इस लिए उठा रहे हैं क्या गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस मात्र एक औपचारिकता है। पुलिस को अपराध की सूचना देना और पुलिस की गैरकानूनी गतिविधियों को बेनकाब करने अपराध है ? क्या पत्रकार सिर्फ पुलिस विभाग और सूचना विभाग की विज्ञप्तियों को प्रकाशित करते हुए पुलिस के जयकारे लगाने तक सीमित हो जाएं?

BBC की डॉक्यूमेंट्री पर देशभर में बवाल, SFI का ऐलान, कोलकाता की यूनिवर्सिटी में भी होगी स्क्रीनिंग

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करके बनाई गई बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जेएनयू में जमकर हंगामा हुआ। लेफ्ट संगठन इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर अड़े हुए हैं। यह मामला केवल जेएनयू का नहीं है बल्कि केरल में भी मंगलवार देर शाम कई कॉलेजों में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। अब लेफ्ट के छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कोलकाता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में बैन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान कर दिया है। एसएफआई की तरफ से कहा गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में 27 जनवरी को यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी।

भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन

'BBC's Ondia: The Modi Question'नाम की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल थण नहीं रहा है। एक तरफ विपक्षी दलों से जुड़े संगठनों और लेफ्ट संगठन इसकी स्क्रीनिंग पर अड़े हैं तो दूसरी तरफ भाजपा युवा मोर्चा इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। एसएफआई के ऐलान के बाद केरल एर्नाकुलम के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से

विक्टोरिया कॉलेज तक भाजपा युवा मोर्चा ने मार्च निकाला। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया। सूत्रों का कहना है कि बैन के बावजूद एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम के कई कॉलेज में मंगलवार देर शाम इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। केरल की सत्ताधारी सीपीआई (एम) के डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि केवल दक्षिणी राज्यों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। डीवाईएफआई की स्टेट सेक्टरी वीके सनोज ने कहा था कि सरकार इसे छिपाने की कोशिश कर रही है लेकिन इसको दिखाने में कोई देश विरोध नहीं है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि देश की संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का खिवाड़ नहीं होना चाहिए। इसके बाद अनिल एंटनी ने बुधवार को कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने कहा था, भाजपा से मतभेदों के बाद भी मुझे लगता है कि एक दूसरे देश का चैनल लंबे समय से पूर्वाग्रह से ग्रसित रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रसारक बीबीसी को भारतीय संस्थानों पर तरजीह देना हमारी संप्रभुता को कमजोर करना है।

डकैती एवं हत्या के मामले के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

मथुरा। मथुरा जिले की एक अदालत ने डकैती और हत्या के मामले के चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुमार्ने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 27 अगस्त 2018 की रात चार बदमाशों ने राया थाना क्षेत्र स्थित गोपाल शर्मा नाम के व्यक्ति के घर में डकैती डाली थी और उन्होंने इस दौरान शर्मा की बेटी को लाठी-डंडों से इस कदर पीटा था कि उसकी मौत हो गई। इस मामले में हरियाणा निवासी हारून, सलीम, अनवर और सवान को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) नितिन पांडे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को सभी चार अभियुक्तों को डकैती और हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुमार्ने की सजा सुनाई।

हिमाचल प्रदेश के विकास के साथ कोई समझौता नहीं होगाः ठाकुर

शिमला। एजेंसी

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पदभार सम्भालते ही पूर्व सीएम जयराम ठाकुर सुक्खू सरकार पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को ओपीएस दीजिए, लेकिन संस्थान बंद और महंगाई बढ़ाकर नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम नई ज़िम्मेवारी के साथ विपक्ष की भूमिका निभायेंगे। जनहित के फ़ैसलों का समर्थन करेंगे, लेकिन जनविरोधी नीतियों का जमकर विरोध करेंगे।

जयराम ठाकुर ने कहा अगर कांग्रेस सरकार जनहित में निर्णय नहीं लेगी तो हम पूरी ताकत के साथ निर्णय का विरोध करेंगे। प्रदेश के विकास के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार की शुरुआत अच्छी नहीं रही एसी हम अपेक्षा नहीं थी, जिस प्रकार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सहजता और सरलता के बारे में चर्चा होती थी पर जो काम उनकी सरकार ने किए वह उनके व्यवहार के विपरीत है। पूरे प्रदेश में कार्यालयों को बंद किया गए जो की प्रदेश हित में नहीं है।ऐसा पहली बार हुआ है की किसी सरकार के एक साल के कार्यकाल का रिव्यू हुआ है, यह बंद करना का सिलसिला ठीक नहीं। आने वाले समय में सरकार 5 साल के निर्णय का भी रिव्यू कर सरकती है। विधानसभा सत्र में तीन दिन तक वॉक आउट हुआ, जनता में रोष है। इस सरकार को अपने फैसलों के बारे में फिर सोचना चाहिए। हिमाचल के इतिहास में पहली बार इतने काम अंतर के साथ कोई सरकार बनी है। जयराम ने कहा कि हमारी सरकार कि योजनाओं का नाम बदले जा रहे है।

जो एक ग़लत परंपरा है। 11 दिसंबर को सरकार ने शपथ ली और बिना कैबिनेट के ही पूर्व सरकार के फ़ैसलों को निरस्त किया। जनहित में खोले हुए संस्थानों को भी बंद किया गया, जो ग़लत है। पूर्व सीएम ने कहा सुक्खू सरकार ने डीज़ल पर वैट बढ़ाया और जनता पर बोझ डाल दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक और परंपरा शुरू होने जा रही है अब हिमाचल प्रदेश की योजनाओं के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपई के नाम योजनाओं को अब हिमाचल में राजीव गांधी के नाम पर रखा जा रहा है, यह कोई स्वस्थ परंपरा नही है। अटल जी के नाम पर हमने डे बोर्डिंग स्कूल की योजना शुरू की, कई बोर्डिंग स्कूलों का तो शिलान्यास भी हो गया पर अब इस योजना का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा जा रहा है। अटल जी नाम हटाना सही नहीं, अटल जी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते थे और हिमाचल के लोग भी उनसे तहे दिल से जुड़े थे।जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के गरीब लोगो ने भी सरकार को वोट डाला है, उनके वोट का सम्मान रखना चाहिए, डीजल की दामों को बढ़ाना सही नहीं इस हिमाचल में महंगाई आएगी।

हिमाचलः मनरेगा मजूदरों की ऑनलाइन हाजिरी का विरोध जारी, अब इन प्रधानों-उपप्रधानों ने सौंपा ज्ञापन

नूरपुर। एजेंसी

हिमाचल में मनरेगा मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी लगाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अब जिला कांगड़ा के विकास खंड नूरपुर और विकास खंड फतेहपुर के तहत आती पंचायतों के प्रधानों उपप्रधानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नूरपुर विकास खंड के अंतर्गत पंचायतों के प्रधानों और उपप्रधानों ने सोमवार को पंचायतों में ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह के माध्यम से सीएम और पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन भेजा। पंचायत प्रतिनिधि उदय पठानियाए सिकंदर राणा और अभिलाषा चिब ने ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि सरकार का मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की ऑनलाइन हाज़िरी का फ़रमान समझ से परे है। इनकी माने तो कई पंचायतों के सदस्य पूरी तरह अनपढ़ है जिन्हें स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है और कई सारे सदस्य ऐसे है जिनके पास स्मार्टफोन फ़ोन भी नहीं है। ऐसे में वो सदस्य ऑनलाइन हाजिरी कैसे लगाएं। इन पंचायत प्रतिनिधियों की मांग है कि पहले सरकार सभी को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए और सभी को ट्रेनिंग मुहैया करवाई जाए। वही कई प्रतिनिधियों का कहना है कि बहुत सारे क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या है। जब सिग्नल ही नहीं होगा तो यह प्रक्रिया कैसे अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस आदेश को वापिस ले और जिस तरह पूर्व में काम चल है उन्हें चलने दें नहीं तो सभी विकासकार्य पूरी तरह बंद ही जाएंगे। टाइड-एन्टाइड की रेशों 70-30 करने को की अपील = इसी तरह से विकास खंड फतेहपुर के प्रधानों की बैठक सोमवार को रेस्ट हाऊस फतेहपुर में हाड़ा प्रधान सुशील कालिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक बारे जानकारी देते हुए पंचायत मिंता प्रधान सुशील शर्मा ने बताया मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी का हम सब प्रधान विरोध करते हुए सरकार से अपील करते हैं कि नेटवर्क समस्या के कारण ऑनलाइन हाजिरी लगाना परेशानी बन रही है। इसलिए जैसे पहले हाजिरी लगाई जाती थीए उसी प्रक्रिया को दोबारा अपनाया जाए।

सीएम भगवंत मान की एचयूएल और महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप से मीटिंग

लुधियाना। एजेंसी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुंबई के दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने हिंदुस्तान यूनी लिवर के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसी कंपनी का नाभा में केचप का प्लांट लगा, जिसमें टमाटर नासिक से लाया जाता है। कंपनी के अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि अब वह प्लांट में इस्तेमाल होने वाले टमाटर को पंजाब से ही लेंगे। इससे कंपनी को मालभाड़े में बचत होगी। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ट्वीट किया।

उन्होंने लिखा कि पंजाब की धरती टमाटर की खेती के लिए बहुत अनुकूल है। इस फसल से किसानों को काफी मुनाफा होगा। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ पंजाब में निवेश करने को लेकर बैठक की। इसके साथ सीएम ने महिन्द्रा एडं महिन्द्रा के अधिकारियों से भी मीटिंग की। पंजाब में सैर सपाटा वाले प्रोजेक्ट्स पर महिन्द्रा ने निवेश करने को लेकर दिलचस्पी दिखाई। ट्रैक्टरों के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। वही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लालडू नजदीक स्वराज ट्रैक्टरों के प्लांट के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान अरविंद मफ्तलाल ग्रुप के अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री मान ने पंजाब में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। बता दें फाजिल्का की तरफ काटन अधिक है। मफ्तलाल ग्रुप यदि निवेश करता है तो उन्हें काफी लाभ मिलेगा। मफ्तलाल ग्रुप को भी पंजाब इन्वेस्ट सम्मेलन का निमंत्रण पत्र दिया गया। बता दें फरवरी में एसएएस नगर, मोहाली में पंजाब इन्वेस्ट सम्मेलन सरकार द्वारा करवाया जा रहा है, जिसे कामयाब करने के लिए पंजाब सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान मुंबई के कारोबारियों को पंजाब इन्वेस्ट सम्मेलन में शामिल होने के लिए न्योता दे रहे।

युवाओं को मिलेगा रोजगार

पंजाब में यदि मुंबई के कारोबारी निवेश करते हैं तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस दौरे से राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पंजाबी फ़िल्म उद्योग पहले ही बहुत बड़ा है और यह प्रस्तावित फ़िल्म सिटी इसको व्यापक प्रसार का मौका देगी। बताया जा रहा है कि यदि इन्वेस्ट सम्मेलन कामयाब रहता है तो करीब 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। देश में निवेश के लिए पंजाब सबसे पसंदीदा स्थान है और राज्य में नए निवेश के लिए हर संभव यत्न सरकार द्वारा किए जा रहे हैं।

सिंगल विंडो सिस्टम को करेंगे मजबूत

मुख्यमंत्री ने निवेशकों की सुविधा के लिए पंजाब के यूनिफाइड रेगुलेटर और सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत करने पर अभी तक जोर दिया है। पंजाब में कारोबार करने वालों को अलग-अलग दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार सिंगल विंडो सिस्टम से एक ही जगह पर सभी सहूलतें देने की तैयारियों में है।

सितंबर महीने में जर्मनी भी कर चुके दौरा

सूबे के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 11 से 18 सितंबर तक जर्मनी का भी दौरा कर चुके हैं। सीएम मान म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट और बर्लिन में अपने प्रवास के दौरान बीएमडब्ल्यू, बेवा और अन्य प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। इसी तरह तमिलनाडु के कारोबारियों से भी सीएम मुलाकात कर चुके हैं।

पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर ने की थी शुरुआत

10 वर्ष पहले पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने इन्वेस्ट पंजाब की शुरुआत की थी। उन्होंने उस समय दावा किया था कि पंजाब में 65 हजार करोड़ का निवेश किया गया है। सुखबीर ने विधानसभा चुनाव में भी उद्यमियों से अपना विजन शेयर करते हुए कहा था कि बिल्ड पंजाब, इन्वेस्ट इन पंजाब एंड प्रमोट पंजाब ही आने वाली शिअद-बसपा सरकार का विजन होगा। सुखबीर ने कहा था कि पंजाब की मौजूदा इंडस्ट्री को अपग्रेडेशन, प्रमोशन एवं नए निवेश के लिए तैयार करने के लिए तीन से पांच फीसद तक इंट्रेस्ट सब्सिडी की जरूरत है।

कैप्टन के समय साढ़े 4 साल में 99 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट

पूर्व सीएम कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के समय पंजाब इन्वेस्टर की रिपोर्ट मुताबिक साढ़े 4 वर्ष में 99 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए। जबकि इस इन्वेस्टमेंट को लेकर चन्नी ने कैप्टन को घेरा था।

उन्होंने कहा कि कैप्टन ने कोई निवेश नहीं करवाया। कैप्टन अमरेन्द्र के आईटी सेल के मुताबिक साइकिल, एग्री और फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, फार्मास्युटिकल, केमिकल, टैक्स्टाइल, अलॉए और स्टील सेक्टर, इंजीनियरिंग, ऑटो कॉम्पोनेंट्स, ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोत, आईटी सेवाएं, शिक्षा, रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा में निवेश हुआ है। यह निवेश अमेरिका, यूके, यूएई., डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर समेत विभिन्न देशों की कंपनियों द्वारा किया जाने का दावा रहा है।

शिवराज कैबिनेट की बैठक

महिला स्व सहायता समूहों को 3 लाख तक के लोन के ब्याज में 2 फीसदी की भरपाई सरकार करेगी

भोपाल एजेंसी।

आज मंत्रालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के बाद मप्र सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कल ओरछा में केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा रामराजा के बाल लोक बनाने और चित्रकूट में वनवासी राम लोक बनाने की घोषणा की थी। सिंगरौली में 25 हजार से ज्यादा लोगों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्लॉट दिए थे। ये दोनों दिन मप्र के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।

कैबिनेट में 2 फरवरी को दिल्ली में बने नए मप्र भवन का लोकार्पण होगा। सभी मंत्री दिल्ली में रहेंगे, उसी दिन मंत्रिमंडल की बैठक भी दिल्ली में होगी। 5 से 25 फरवरी तक निकलने वाली विकास यात्रा की समीक्षा 5 फरवरी के पहले करने के सभी मंत्रियों को निर्देश दिए। आजीविका और शहरी आजीविका मिशन में महिला स्व सहायता समूह की राशि तीन लाख तक बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2त्न ब्याज की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी जो अब तक 3त्न लगता था ब्याज की छूट देने का बड़ा फैसला हुआ। जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को सीहोर में सूर्या फाउंडेशन ने जिस प्रकार से एक परिसर को लिया है उसी तरह से यदि कोई और संस्थाएं इस काम के लिए आगे आती हैं तो उन्हें यह काम सौंपा जाएगा।

नगरी निकाय में अधोसंरचना निर्माण योजना की स्वीकृति के लिए योजना शुरू की है इस योजना की अवधि 2 साल तक रहेगी 2022-23 और 2023-24 रहेगी। इस योजना में कुल 800 करोड रुपए खर्च होंगे। 2022-23 के लिए 200 करोड रुपए के बजट का प्रावधान है। बाकी 600 करोड़ की मंजूरी का प्रावधान भी आज की कैबिनेट बैठक में मंजूर हुआ। नर्मदा पुरम मुहासा बावड़ी मार्ग पर ह्वद्ध-22 तवा नदी पर फोर लोन स्तरीय पुल के लिए 148.97 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। सिवनी जिले के बंडोल सागर चंदौरी कला सड़क निर्माण के लिए 108.97 करोड़ की स्वीकृति दी गई। सीहोर जिले के बकतरा भारकच्छ शाहगंज मार्ग के लिए 121.83 करोड़ की स्वीकृति।

सीहोर के बकतरा सिया गहन सागपुर, बोदरा मार्ग के आंतरिक निर्माण के लिए 108.17 करोड़ की स्वीकृति। मुरैना जिले की एबीसी कैनाल निर्माण के लिए 106.7 करोड़ की मंजूरी। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में पीजी सीट बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई यहां 85 सीटें बढ़ाने के लिए 101.46 करोड़ की स्वीकृति। लोक परिसंपत्ति विभाग ने गुना के पुराना बंगला को 3 करोड़ 59 लाख 27 हजार में देने की मंजूरी।

भोपाल के लांबाखेड़ा में 6 करोड़ 94 लाख 11 हजार में आवंटित करने का फैसला। संविदा शाला शिक्षक की कंडिका 5 में उल्लेखित प्रयोगशाला शिक्षक में प्रतिस्थापित करने में फैसला हुआ इस फैसले के बाद अनुकंपा नियुक्तियों की दिक्कतें दूर होंगी।